International Commission of Jurists' report on Kashmir

*135. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the International Commission of Jurists have, in their report, recorded findings on various aspects of the Kashmir problem;

(b) which of the Commission's findings have been rejected and which have been accepted by the Government of India;

(c) what is the point-by-point refutation of Government, of the Commission's findings which have been rejected; and

(d) what opinion has been given by Prof. Maurice Mendelson on the findings of the Commissions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (d) Relying largely on media and NGO reports, the International Commission of Jurists has criticised the Government in respect of alleged human rights violations in J&K, while acknowledging some of the steps taken to further human rights protection in the State.

The report has acknowledged that large scale violations of human rights has been committed by the militants. The report, however, fails to display understanding of the fact that militant violence amounts to organised violation of human rights, and poses difficulties for maintenance of law and order in the State.

The ICJ report states that the Simla Agreement is clearly binding on Pakistan and deprives the Pakistan Government of locus standi to intervene in Jammu and Kashmir. The report also acknowledges that ISI has been giving assistance to militants in J&K.

The ICJ report has come out with notions of the exercise of right to self-determination which are contrary to established principles of international law. Prof. Mendelson in his independent opinion on the report has brought out its inconsistencies and clarified the situation.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन

*136. श्री रामजेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये गत वर्षों में अनेक प्रयास किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन प्रयासों के फलस्वरूप देश में विदेशी पूंजी निवेश हेतु कई प्रस्ताव भी प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो जून, 1991 से जनवरी 1995 तक विदेशी पूंजी निवेश संबंधी कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये तथा इनके माध्यम से कितनी मात्रा में पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इन प्रस्तावित पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव क्रियान्वित भी किये गये हैं; यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव क्रियान्वित किये गये तथा उनमें कितना पूंजी निवेश किया जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न

क्षेत्रों में पूंजी निवेश, इसमें विदेशी पूंजी निवेश शामिल है, को बढ़ावा दे रही है। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 2528 करोड़ रु० के विदेशी निवेश वाले 195 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(घ) 529 करोड़ रु० के विदेशी निवेश वाले 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। आमतौर पर परियोजना को लागू करने में लगभग 2–3 साल लग जाते हैं।

रेलवे जोनों का बनाया जाना

137. **श्री आरु मोहम्मद :**

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये रेलवे जोन बनाये गये हैं;

(ख) इन नये जोनों को बनाये जाने के लिये कौन-सा मापदंड अपनाया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला जोन कौन-सा है ; और

(घ) दूसरे जोनों की तुलना में सर्वाधिक कार्यभार तथा सर्वाधिक संचालन गतिविधियों वाला रेलवे जोन कौन-सा है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में किसी नये जोन का सृजन नहीं किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे ने अधिकतम लाभ दर्शाया है।

(घ) कार्यभार सूचकांक के आधार पर मध्य, उत्तर, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम रेलों पर काम का अधिकतम दबाव है।

Capacity for LPG distributor agencies

*138. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether there is any prescribed capacity for LPG distributor agencies in terms of single cylinder unit; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) The existing ceiling on the refill sales by the distributors in different towns/cities is as under:—

Towns/Cities with population	No. of refills per mensem
(a) Upto 10 lakhs	4,000
(b) Over 10 lakhs to 20 lakhs	5,000
(c) Over 20 lakhs to 40 lakhs	6,000
(d) Delhi, Madras and Calcutta	6,500
(e) Bombay	8,000